P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय स्कूल शिक्षा सुधार एवं सुझाव

सारांश

आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए बढ़ती आवश्यकता विकासशील देशों के लिए मानवीय, वित्तीय, तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर कई प्रकार की नई चुनौतियों को उजागर कर रही है। स्कूल शिक्षा ही समाज में यश एवं प्रतिष्ठा का मूल केंद्र है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा एक पीढ़ी अपनी आने वाळी पीढ़ी तक संस्कृति का हस्तांतरण करती है। यह समाज में प्रभावी और कुशल (Efficient And Effective) ढंग से जीने के लिए मनुष्य को तैयार करती है। शिक्षा ज्ञान पर आधारित समाज (Knowledge Based Society) में एक कुशल सदस्य बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान (Skills And Knowledge) प्रदान करती है। यह व्यक्ति के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है और जीवन की चुनौतियों से निपटने में मद्द करती है, इसलिए हरेक देश वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा की अपनी ही एक अलग प्रणाली विकसित कर रहा है।

इस शोधपत्र को दो भागों में बांटा गया है : भाग–1 में भारतीय सरकार के द्वारा स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए की गई पहलकदमियों का वर्णन किया गया है और भाग–2 में स्कूल शिक्षा क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव दिए गये हैं।

बलबीर कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
डिपार्टमेंट ऑफ़ इवनिंग
स्टडीज–मल्टी डिसीप्लिनरी
रिसर्च सेंटर,
पंजाब युनिवर्सिटी,
चण्डीगढ़

मुख्य शब्द : स्कूल शिक्षा, सुधार, सुझाव, प्रयास।

प्रस्तावना

स्कूल शिक्षा व्यवस्था समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्र की प्रगति भी उन मनुष्यों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है जो कि स्कूल और कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। स्कूल शिक्षा एक औपचारिक तरीका है जिसको बच्चे का दूसरा घर (Second Home) भी कहा जाता है और जहां पर वह अपने ज्ञान व क्षमता को बढ़ाता है। भारत में स्कूल शिक्षा को एक बड़े पैमाने पर प्रदान किया जा रहा है। इसको बेहतर बनाने के लिए समय–समय पर स्कूल शिक्षा प्रशासन के द्वारा बहुत सारे प्रयास किये गये, लेकिन विद्यार्थियों के एक बड़े वर्ग को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना सरकार के लिए एक समस्या बनी हुई है परन्तु फिर भी स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाना सरकार का पहला उद्देश्य है ताकि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

साहित्यावलोकन

तातेड़, सोहन राज व शर्मा, मनीषा (2012), इन्होंने प्राचीन और आधुनिक भारतीय शिक्षा के बारे में बताया है जो कि सामाजिक–आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। सारस्वत, सीतेश (2016) इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों, नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों व प्राचीन भारतीय शिक्षा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, इसके साथ ही इन्होंने सामाजिक शिक्षा पर भी बल दिया है। शर्मा, बिन्दु एवं शर्मा विभा (2018) इन्होंने माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता लाने के लिए किये गए प्रयासों का वर्णन किया और नवीन पाठ्यक्रम व तकनीकी, स्कूली ढ़ांचे में सुधार और दाखिले व मूल्यांकन प्रकिया में सुधार पर बल दिया है।

शोधपत्र का उद्देश्य

भारत में स्कूल शिक्षा स्तर पर एक बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसलिए प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किये गये प्रयासों को ळोगों के सामने लाना है ताकि स्कूल शिक्षा सम्बन्धी सरकार की पहलकदमियों को आंका जा सके और इनके मार्ग में आने वाली समस्याओं को समझा जा सके व समुचित समाधान सुझाए जा सकें।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

शोधपत्र का महत्व

स्कूल शिक्षा एक मुख्य विषय है, इस शोधपत्र के द्वारा स्कूल शिक्षा क्षेत्र की स्थिति को समझा जा सकता है। भूतकाल में बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लाई गईं परन्तु उनमें कुछ कमियां देखी जा सकती हैं। शोधपत्र में दिए गए सुझावों द्वारा भविष्य में स्कूल शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता लाई जा सकती है यदि सरकार इन सुझावों को निष्ठापूर्वक लागू करने का प्रयास करेगी।

भारत सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहल

भारत में 1976 से पहले शिक्षा प्रदान करने की सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी लेकिन 42 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। परिणामस्वरूप, शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र और राज्य सरकारों के पास आ गया, जिसके बाद से स्कूल शिक्षा का विस्तार आरम्भ हुआ।

केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा से सम्बन्धित नीति बनाने में पहल की और अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जिनका निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया जा सकता है :–

1. कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 (National Policy on Education) की स्थापना की गई ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके।
2. शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती असमानताओं को दूर करने व स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए नई शिक्षा नीति 1986 (New Policy on Education) और कार्य योजना 1992 (POA) लागू की गई जिसने स्कूल शिक्षा को एक बुनियादी ढ़ांचा प्रदान किया।
3. 86 वां संवैधानिक संशोधन 2002 में पास किया गया और स्कूल शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बना, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया।
4. माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करने व इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (SSA) मार्च 2010 में शुरु किया गया।
5. भारत सरकार निश्चित दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने पर बल दे रही है और स्कूलों में अनेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अग्रसर है जैसे कि :–पर्याप्त शिक्षा भवन, लैबोरेटरीज, पुस्तकालय, कला और शिल्प कक्ष, लड़कों व लड़कियों के लिए अलग शौचालय, पीने के पानी की सुविधा और स्कूलों में बिजली व इन्टरनेट की व्यवस्था।

इसके साथ ही, भारत सरकार अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) पिछड़े वर्गों, लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को भी स्कूल शिक्षा की इस मुख्यधारा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के अलावा, देश में माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए कुछ अन्य संगठन भी काम कर रहे हैं जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है :–

चित्र : 1 माध्यमिक शिक्षा संगठन

- केन्द्रीय विद्यालय संगठन (Kendriya Vidyalaya Sangathan)
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT)
- नवोदय विद्यालय समीति (Navodaya Vidyalaya Samiti)
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (National Institute of Open School)
- केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (Central Tibetan School Administration)

Source: www.schooleducation

माध्यमिक स्कूल शिक्षा स्तर छात्रों के सर्वपक्षीय विकास में अतुलनीय भूमिका अदा करता है, सरकार इस स्तर पर अनेकों संस्थान चला रही है। इस प्रकार समाज के सभी वर्गों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001–02 में सर्व–शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan) योजना शुरु की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों का सही प्रबंधन करना तथा सामाजिक असमानता को कम करना था। यह कार्यक्रम स्कूल शिक्षा में सुधार और 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का एक प्रयास है व समाज के सभी वर्गों को स्कूल शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अतिरिक्त, एलीमेंट्री शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिनको चित्र 2 में दिखाया गया है :–

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-11* July- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

चित्र : 2 एलीमेंट्री शिक्षा के लिए अन्य योजनाएं

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना (Operation Blackboard Yojana)

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya)

प्रारम्भिक शिक्षा कोष (Prarambhik Shiksha Kosh)

ग्रामीण शिक्षा समीतियां (Village Education Committees

अभिभावक-शिक्षक संघ (Parent-Teachers Associations)

Source: www.schooleducation

सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है तथा प्राइमरी तक के स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के तहत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय माध्यमिक स्कूल शिक्षा स्तर पर पढ़ने वाली गरीब परिवारों की छात्राओं के लिए स्कूलों में पढ़ने के साथ–साथ रहने की व्यवस्था करते हैं। ग्रामीण स्कूल शिक्षा में नवीनता व सुधार लाने के लिए गांव स्तर पर ग्रामीण शिक्षा समीतियों का गठन किया गया है ताकि इनके सदस्य स्कूल शिक्षा प्रबन्ध में अपना योगदान दे सकें। स्कूल शिक्षा के दौरान छात्रों के माता–पिता उनकी गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं इसलिए अभिभावक–शिक्षक संघों की मदद से छात्रों की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। इसके साथ ही, स्कूल शिक्षा में गुणात्मक और संख्यात्मक सुधार लाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छात्र उन्मुखी शिक्षा (Student Centric Education) पर बल दिया गया है व स्कूलों में उचित सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा में निजी निवेश (Private Investment) को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर्पस (NCC) खेल, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, योग शिक्षा और स्काउटिंग आदि गतिविधियों को स्कूल शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि देश और समाज में एक सजग वातावरण पैदा किया जा सके। महिला सशक्तिकरण के लिए स्कूलों में कार्यरत महिलाओं के नेटवर्क को मजबूत बनाने, लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा का विस्तार करने, लिंग (Gender) जागरूकता कार्यक्रमों और लिंग संवेदनशील पाठ्यक्रम के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारत सरकार की अन्य पहलकदमियां

भारत सरकार ने स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए ताकि गुणवत्ता शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इनका वर्णन इस प्रकार है :–

1. भारत सरकार ने शैक्षिक उपग्रह (EDUSAT) सितम्बर, 2004 में स्थापित किया था। यह स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़ता है जिसके द्वारा नवीनतम जानकारियां जुटाई जा सकती हैं और शिक्षा का अधिक से अधिक विकास किया जा सकता है। यह शिक्षा के प्रसार का एक नया व कुशल माध्यम है जिसमें कार्यक्रमों का संचालन राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) के सहयोग से हो रहा है।
2. परिवर्तन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल का उद्घाटन फरवरी 27, 2016 को संचार एवं सूचना तकनीकी विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रशाद के द्वारा किया गया। इस तकनीक के द्वारा स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों का रिकोर्ड जल्दी से तैयार किया जा सकता है और इसे लम्बे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है व आवश्यकता पड़ने पर डाटा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है।
3. भारत में सेमेस्टर सिस्टम ज्यादा पुरानी परीक्षा प्रणाली नहीं है। स्कूलों में इसे परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसने स्कूल शिक्षा को बहुत ज्यादा आसान व तनावमुक्त बना दिया है क्योंकि इसके द्वारा पाठ्यक्रम को दो भागों में बांट दिया गया है परिणामस्वरूप, छात्रों को सभी विषय तैयार करने का उचित समय मिल जाता है और छात्र अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। यह प्रणाली छात्रों व शिक्षकों को साल भर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
4. स्कूलों में प्रयोगशालाएं छात्रों में ज्ञान को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई हैं। भारत सरकार के द्वारा सभी ग्रामीण व शहरी स्कूलों में प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जा रही है, जिसके माध्यम से साइंस क्षेत्र के विद्यार्थियों की शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकती है। इन प्रयोगशालाओं में सरकार के द्वारा जरूरी व नए उपकरण मुहैया करवाये जा रहे हैं।
5. हॉस्टल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत बनते जा रहे हैं क्योंकि घरों से दूर रहने वाले छात्रों के लिए इनका विशेष महत्व है। गर्ल्स हॉस्टल की निर्माण योजना के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण और उन्हें कुशल ढंग से चलाने की व्यवस्था की गई है ताकि लड़कियों तक बिना बाधा के शिक्षा सुविधाएं पहुँचाई जा सकें।

6. छात्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा को तभी जागृत किया जा सकता है जब उन्हें कोई प्रोत्साहन मिले। राष्ट्रीय साधन सह–योग्यता छात्रवृति योजना मई, 2008 में शुरू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें और समाज में अपना स्तर ऊँचा उठा सकें।
7. सरकार के द्वारा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के बच्चों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं, इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) रहने वाले बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इन वर्गों को स्कूल शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।
8. शिक्षण संस्थानों से बाहर भ्रमण छात्रों को किताबी दुनिया से दूर ले जाता है। सरकार छात्रों के लिए शैक्षणिक भ्रमण (Educational Tours) की व्यवस्था कर रही है। शिक्षा विभाग के द्वारा अध्यापकों की देख–रेख में छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए विभिन्न जगहों पर ले जाया जाता है ताकि उनके सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि की जा सके।
9. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान (Save Girl, Educate Girl) भारत में बेटियों की रक्षा, उन्नति के लिए और उनके खिलाफ भेदभाव एवं लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए 22 जनवरी 2015 को एक राष्ट्रव्यापी अभियान "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" शुरू किया गया। 10 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस पर "बेटियों का सलाम राष्ट्र के नाम" विद्यालय स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें गाँव की सबसे ज्यादा पढ़ी–लिखी लड़की को स्कूल में तिरंगा फहराने का मौका दिया गया।

भारत सरकार ने समय–समय पर स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जिनके कुछ अच्छे परिणाम निकले, परन्तु फिर भी कुछ समस्याएं जन्म ले रही हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं।

महत्वपूर्ण सुझाव

आधुनिक समय में स्कूल शिक्षा क्षेत्र दिन–प्रतिदिन विशाळ बनता जा रहा है, जिसके कारण स्कूल शिक्षा में सुधार लाने के लिए किये गए प्रयासों को पूर्ण रूप से लागू करने में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं। स्कूल शिक्षा की इन समस्याओं को निम्नलिखित सुझावों के द्वारा दूर किया जा सकता है।

1. विद्यालय शिक्षा के मन्दिर माने जाते हैं जो कि बच्चों को सही वातावरण प्रदान करते हैं, इसलिए छात्रों और अध्यापकों के मध्य मधुर सम्बन्ध होने चाहिए। स्कूल में सभी छात्रों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए ताकि सभी छात्र अपने आपको स्कूल व्यवस्था का हिस्सा समझें। देश में लगातार बढ़ रही जनसंख्या के कारण आधुनिक स्कूल व्यवस्था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ बनती जा रही है और ये समस्या सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता है।
2. स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त प्राचार्यों और शिक्षकों छात्रों की सुरक्षा, स्कूल की देख–रेख, साफ–सफाई, जनगणना, मतदान और स्कूल स्तरीय कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिससे शिक्षकों पर काम का बोझ दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आ रही है। उनके काम के बोझ को तभी कम किया जा सकता है जब खाळी पड़े पदों को भरा जाएगा। शिक्षा के अधिकार (RTI) एक्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक–छात्र अनुपात 40:1 तक लाया जाना चाहिए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का कम आना एक बड़ी समस्या है। सभी सीनियर सेकेंडरी और उच्च स्कूलों में जहां पर EDUSA की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है वहां पर खराब बैटरियों के कारण बिजली को बैकअप रखने की व्यवस्था नहीं है, इन स्कूलों में बैटरियों की समुचित व्यवस्था की जानी चालिए ताकि बिजळी न होने की स्थिति में भी विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकें और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। इसके अतिरिक्त स्कूलों में तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चालिए।
4. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखनी आवश्यक है। शिक्षा विभाग अपने कार्यालयों व देश के सभी स्कूलों में कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर की जगह पर प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली के द्वारा शुरू करने के लिए प्रयासरत है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मशीनें लगवाई जानी चाहिए जिससे शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के आने–जाने के समय की जानकारी शिक्षा विभाग के पास समय पर पहुँचती रहेगी और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
5. पानी जीवन का आधार है जिसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। देश के सभी स्कूलों में पीने के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता नहीं है इसलिए स्कूलों में पीने के पानी के लिए साफ पानी की टंकियों की समुचित व्यवस्था होनी चालिए। इसके साथ ही, स्कूलों में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है इसलिए स्कूलों में इनकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. विद्यार्थियों में समाज और राष्ट्र के प्रति लगन पैदा करने व उनका शारीरिक विकास करने के लिए सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में NSS व NCC शुरू की जानी चाहिए। स्कूल में स्टाफ, छात्र और छात्राओं के

लिए अलग–अलग शौचालय बनवाये जाने चाहिए व उन तक पहुँचने के लिए पक्के रास्ते का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि हरेक स्कूल में एक सही आकार के खेल के मैदान की व्यवस्था की जाए।

7. जन–सहभागिता किसी भी संस्थान को सही तरीके से चलाने के लिए एक मूल मंत्र है क्योंकि स्थानीय लोगों के द्वारा समस्या को अधिक कारगर ढ़ंग से सुलझाया जा सकता है, इसलिए स्कूल प्रबन्ध व स्कूल शिक्षा सुधार के लिए गांव के सभी वर्गों के लोगों जैसे : सरपंचों, पंचों, बच्चों के अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग को आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि स्कूल प्रबन्ध को पहले से अधिक बेहतर बनाया जा सके और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
8. आधुनिक समय में शिक्षक नई तकनीकी जैसे : Whattsapp, E-mail, Facebook, Phone Call और Messages आदि का सहारा लेकर व उसका भरपूर इस्तेमाल करके बच्चों व उनके परिवार से सीधा सम्पर्क रख सकते हैं। इस तरह वे छात्र की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से परिचित हो सकते हैं व छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं से उनके परिवार को परिचित करवा सकते हैं। परिणामस्वरूप छात्रों को समाज में सही मार्ग पर चलाया जा सकता है।
9. स्कूल शिक्षा छात्रों के सिर्फ मानसिक ज्ञान में वृद्धि करती है। छात्रों को विद्यालय परिसर से बाहर के परिवेश से परिचित करवाना भी आवश्यक है इसलिए सरकारी स्कूलों के छात्रों को अलग–अलग जगह पर भ्रमण के लिए ले जाया जाना चाहिए ताकि उन्हें व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान मिल सके। छात्रों की सुरक्षा स्कूल की जिम्मेवारी है इसलिए शैक्षणिक भ्रमण के दौरान उनकी सुरक्षा का ख़ास ध्यान रखा जाना चाहिए।
10. प्राकृतिक आपदा किसी भी समय मानव जीवन को प्रभावित कर सकती है और स्कूल शिक्षा संस्थान भी इससे अछूते नहीं हैं इसलिए सरकारी स्कूलों में बच्चों कों नकली सुनिश्चित अभ्यास (Mock Drill) करवाया जाना चाहिए ताकि आपदा के समय बच्चे अपनी और दूसरों की सहायता कर सकें व प्राकृतिक आपदा के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में समाज में जागरूकता फैला सकें।
11. छात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता छात्रों के जीवन में साकारात्मक बदलाव ला सकती है। मेधावी छात्रों को स्कूलों में अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ताकि कमज़ोर वर्गों के बच्चे स्कूल शिक्षा में बने रहें और अपना विकास कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि स्कूल शिक्षा स्तर पर छात्रवृत्तियों के बारे में जानकारी अधिक से अधिक फैलाई जानी चाहिए।

नीतियों को सही रूप से लागू करना उतना ही आवश्यक है जितना कि उनको तैयार करना, इसलिए उपर्लिखित सुझावों को सही प्रकार से लागू करके ही स्कूल शिक्षा क्षेत्र में साकारात्मक परिवर्तन ळाये जा सकते है और समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

स्कूल शिक्षा विद्यार्थियों के जीवन का आधार है जिसे और अधिक मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के निर्देशन में शिक्षा विभाग को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने पर बल देना चाहिए। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने एवं विद्यार्थियों के चहुँमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए, क्योंकि यदि नीतियों को बनाने की अपेक्षा उनको लागू करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, तभी स्कूल शिक्षा की समस्याओं से निपटा जा सकेगा और इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। एक कुशल शैक्षिक प्रशासन की मदद से स्कूल शिक्षा की समस्याओं से कुशलतापूर्वक निपटा जा सकता है और स्कूल शिक्षा हरेक गांव, शहर और कस्बे के बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है व शिक्षा के द्वारा समाज का स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। स्कूली शिक्षा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फैसले भारत सरकार द्वारा लिए जाने चाहिए ताकि छात्रों को अध्ययन करने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *तातेड़, सोहन राज व शर्मा, मनीषा (2012), भारतीय प्राचीन एवं नवीन शिक्षा प्रणाली, दीपक पब्लिशर्स, जयपुर, पेज–5–10.*
2. *सारस्वत, सीतेश (2016), समकालीन भारत और शिक्षा, विकास पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पेज–15–25.*
3. *रतन, विजयलक्ष्मी (2003), "एजुकेशन इन लास्ट फिफ्टी इयर्स", योजना, वॉल्यूम 47, नम्बर 5, पेज–18–23.*
4. *वशिष्ट, एस. आर. (1994), एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पेज–8–17.*
5. *भाटिया, के. के. (2005), डेवळपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पेज–20–35.*
6. *शर्मा, बिन्दु एवं शर्मा, विभा (2018), Secondary And Senior Secondary School Education in India:An Assessment And Reforms, International Journal of Research in Social Sciences, वॉल्यूम 8, नम्बर 7, पेज–25-30.*